

शुद्ध पानी देने को बिहार की राह चली केंद्र सरकार

पटना। फ्लोराइड, आर्सेनिक तथा आयरन से प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की बिहार सरकार की योजना की तर्ज पर केंद्र भी ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग योजना बनाएगी। नौ व दस सितंबर को दिल्ली में चली कार्यशाला में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल कैसे मुहैया कराया जाए इस पर मंथन हुआ।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के उच्चाधिकारियों द्वारा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए नीति आयोग को प्रस्ताव भेजने की बात कही गई। कार्यशाला से लौटे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों

के मुताबिक केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल देने की योजना बना रहा है। केंद्र की योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे, योजना पर काम करने में आर्थिक सहयोग, प्रचार-प्रसार पर केंद्रित रहेगी। अब तक गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए पेयजल के कुल बजट 60 फीसदी से अधिक हो सकता है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि केंद्र के अफसरों ने बिहार की ई-चापाकल मोबाइल एप की सराहना की। इसका अनुसरण करने को अन्य राज्यों से कहा।